

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3962

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

औद्योगिक परिवर्तन और सतत विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता

3962. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज एवं विनिर्माण प्रधान क्षेत्रों, विशेषकर इस्पात, एल्युमीनियम एवं खनिज आधारित उत्पादों के प्रमुख उत्पादक राज्यों के लिए, कम कार्बन उत्सर्जन और सतत औद्योगिक परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया है;

(ख) क्या हरित इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण, बैटरी भंडारण एवं हाइड्रोजन मूल्य शृंखला जैसे उभरते क्षेत्रों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, निवेश और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी के संबंध में कोई डेटा या विश्लेषण उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं एवं वैश्विक कार्बन संबंधी विनियमों के संदर्भ में कोयला एवं खनिज आधारित उद्योगों पर राजकोषीय निर्भरता से उत्पन्न होने वाले लाभ-हानि का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो ओडिशा जैसे औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में कार्यबल के नए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आपूर्ति शृंखला विविधीकरण सहित न्यायसंगत एवं समावेशी औद्योगिक परिवर्तन में सहायता हेतु विचाराधीन नीतिगत ढांचों, प्रोत्साहनों या औद्योगिक कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): जहां तक भारी उद्योग मंत्रालय का संबंध है, इस तरह का कोई आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत ने नवंबर 2021 में यूएनएफसीसीसी के 26वें सत्र (सीओपी 26) में 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसके अनुसरण में, भारत ने नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी को अपनी दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाली विकास रणनीतियाँ (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत कीं, जो 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सात प्रमुख रणनीतिक परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक ढांचा प्रदान करती हैं। रणनीतिक परिवर्तनों में से एक में अर्थव्यवस्था-व्यापी स्तर पर विकास को उत्सर्जन से अलग करने को बढ़ावा देना और एक कुशल, नवोन्मेषी कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक प्रणाली का विकास करना शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक प्रणाली के घटकों में ऊर्जा दक्षता में सुधार; प्रक्रिया और ईंधन में बदलाव, और विद्युतीकरण; सामग्री दक्षता और पुनर्चक्रण में वृद्धि; हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है।

\*\*\*